industry rules. It is only unfair because there was some problem, some misuse was being made by the World Bank Officer. To certain that they have written to Air India. As far as the Airlines practice is concerned, this is not unusual. This is not irregular. ... [*Interruptions*] ...

MR. CHAIRMAN: The Minister has answered the question.

SHRI G. G. SWELL: I would like to know whether Mr. Shivdasani has explained his action. Has he given the reason why he did it despite the letter from the World Bank?

MR. CHAIRMAN: I think the Air India Manager has taken it up and warned him accordingly.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, he has already been cautioned. The Regional Director and the Commercial Director have already written to him. More so, this letter was received by Air India Office in August 1991 and this Officer joined only in 1992.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 224.

एक माननीय सदस्य: 223 का क्या हुआ?

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: मेरा ट्रांसफर हो गया 24 तारीख को? मुझे सूचना मिली है कि 24 को है ... *(व्यवधान)* ... मुझे लिखित मिला है कि 24 को है ... *(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: It has been transferred to 20th August. I am told the Members have been informed about it.

*222 *[Transferred to 20th August, 1993]*

*223 *[Transferred to 24th August, 1993]*

New Growth Centres for Gujarat

*224. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI VITHALBHAI M. PATEL: †

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only one growth centre has been sanctioned to Gujarat;

(b) if so, what are the reasons for not sanctioning more growth centres to Gujarat;

(c) whether it is also a fact that sufficient amount to be invested on this project has not been released; and

(d) if so, what are the reasons for not releasing funds required for the growth centre?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) गुजरात के लिये तीन विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं जिनमें से कच्छ, बनासकंठा और भड़ोच जिलों में एक-एक है। केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों के लिये अब तक 3 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Mr. Chairman, Sir, the Government of India have released Rs. 2 crores only for the three growth centres instead of releasing Rs. 2 crores for each centre. So in 1992-93 and in 1993-94, Government have released only Rs. 2 crores, still, they have to release Rs. 6 crores. For 1993-94 also they have to release Rs. 3 crores. In all the Government of India have to release Rs. 9 crores for these centres.

Similarly, IDBI also have to release Rs. 2 crores for each growth centre. Uptill now, not a penny has been released by the IDBI. The Government of Gujarat had set up a Growth Centre Development Corporation. They have taken a loan from Gujarat Industrial Development Corporation to finance these growth centres. May I know from the Minister when she is going to release Rs. 9 crores which is already due to these three growth centres?

श्रीमती कृष्णा साही: सभापति महोदय, यह ग्रोथ सेंटर की जो योजना है, इसके तीन स्तर हैं। एक है बेसिस आफ स्टेट-वाईज़ एलोकेशन, दूसरा है—प्रोसीजर्स फार एप्रेज़ल और उसके बाद राशि आवंटित की जाती है।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं—इनके मूल प्रश्न का अर्थ यही है कि राशि रिलीज़ नहीं की गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि दो केंद्रों में मात्र 12.26 लाख रुपये ईच का खर्च बताया गया है। मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि स्वीकृत केंद्र जो इनका है, गांधीधाम जिला कच्छ में, उसमें आवंटित राशि इनको पचास लाख दी गई है और अद्यतन वित्तीय प्रगति जो है, 12.26 लाख का व्यय हुआ है।

पालनपुर, जिला बनासकंठा के लिए पचास लाख की राशि आवंटित की गई है, जिसमें अद्यतन वित्तीय प्रगति जो है, 12.26 लाख का व्यय हुआ है।

बागरा, जिला भड़ोच में दो करोड़ की राशि इनको आवंटित की गई है। अद्यतन वित्तीय प्रगति 9.19 करोड़ का व्यय हुआ है।

---

† सभा में यह प्र ि श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल द्वारा पूछा गया।

मैं बताना चाहती हूं कि दो केंद्रों में मात्र 12.26 लाख रुपया ईंच का खर्च बताया गया, जबकि केंद्र ने पचास-पचास लाख दे दिया है । बागरा में लगभग नौ करोड़ रुपये का व्यय बताया गया है । इस राशि, अर्थात् 9.19 करोड़ का व्यय बताया गया है । इसका एक-तिहाई, अर्थात तीन करोड़ केंद्र को देना है, जिसमें से दो करोड़ दिया जा चुका है । बाकी शीघ्र दिया जाएगा ।

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Mr. Chairman, Sir, I think the Minister is confused. The Government of Gujarat has already spent Rs. 5 crores. The Centre has to pay them still Rs. 9 crores, not Rs. 3 crores.

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, मैं बिलकुल सही बात बता रही हूं और ठीक बता रही हूं कि भारत सरकार की जो तीस करोड़ की यह आर्थिक योजना है, इसमें मात्र एक-तिहाई, दस करोड़ का हिस्सा आता है और एक-तिहाई के अनुपात में केंद्र सरकार को सहायता की राशि देनी है । अत: आगामी कुछ महीनों में अद्यतन प्रगति के आधार पर एक या दो करोड़ जो इनको देना है, वह दे दिया जाएगा ।

जहां तक इन्होंने आई०डी०बी०आई० वगैरह की चर्चा की है, तो मैं इस विषय में बताना चाहती हूं कि परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के बाद जो कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व है, वह पूर्णतया राज्य सरकारों पर है । अनेक राज्य सरकारों के द्वारा इसके लिए विशेष संगठन को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गई है और इसी तरह से अन्य संस्थाओं को भी दी जाती है ।

समय-समय पर केंद्रीय स्तर पर प्रगति की समीक्षा राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है । जो इन्होंने आई०डी०बी०आई० की चर्चा की है, तो आई०डी०बी०आई० ने बताया है कि वित्तीय संस्थान इस वर्ष से ही अपने हिस्से का भुगतान करना शुरू कर देंगे और एप्रेज़िंग एजेंसी का जो उत्तरदायित्व है, वह राज्य सरकार से परामर्श करके परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार और जो वित्तीय संस्थायें हैं, उनके बीच विचार-विमर्श होता है, उनके बीच पत्राचार होता है और उसके बाद राज्य सरकार से निर्णय लिया जाता है । हम केवल मानिटरिंग करते हैं ।

जो मार्गदर्शन, गाइडलाईन इसके लिए दिया हुआ है और जो क्राइटीरिया फिक्स है, उसके अनुसार ही भारत सरकार राशि का भुगतान करती है । जहां तक राशि की स्वीकृति और विमुक्ति का प्रश्न है, एक साथ पूर्ण राशि नहीं दी जाती है, बल्कि वित्तीय व्यय और भौतिक प्रगति के आधार पर किस्तों में केन्द्रीय सहायता का भुगतान किया जाता है ।

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: May I know from the Minister, what the criteria are for selecting the growth centres? In the State of Gujarat, Sabarkantha district is one of the most backward districts. May I know from the Minister whether she will consider one growth centre for this district also? In the State of Gujarat, there are only three growth centres whereas other States are having 8, 10 and 12 growth centres which have been sanctioned by the Government of India. Will she sanction one more for Gujarat State?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, मैंने जैसा पहले कहा है कि बेसिस आफ स्टेटवाइज़ एलोकेशन एंड प्रोसीज़र फार एप्रूवल यह मैंने इनको बताया है कि तीन स्तर हैं । मैं इन्हें विस्तार में बताना चाहती हूं कि राज्यों के बीच राज्यवार आवंटन . . . *(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Why don't you say you will consider one more centre for Gujarat, instead of going into the detail?

SMT. KRISHNA SAHI: I am coming to the exact point.

राज्यों के बीच जो विकास केन्द्रों का वितरण या जो एलोकेशन है, जो यह चाहते हैं कि क्या और भारत सरकार दे सकेगी, तो भारत सरकार से स्तर से यह संभव नहीं है इसका प्रोसीजर है कि राज्यों के बीच इन विकास केन्द्रों का वितरण राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल और औद्योगिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जाता है और देश भर में 70 विकास केन्द्र 8वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं । जहां तक इन्होंने यह कहा है कि क्या एक और देने का इनके सामने प्रश्न आता है तो मैं इनसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार अगर अनुशंसा करती तो हम अवश्य उसे देखते । लेकिन जनसंख्या, क्षेत्रफल और औद्योगिक पिछड़ेपन के आधार पर गुजरात राज्य को 3 विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं । राज्य सरकार ने सुरेन्द्र नगर के साथ तीन और जिसकी चर्चा मैंने की है केन्द्र के पास प्रस्ताव भेजा था लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच जब विचार-विमर्श हुआ तो गुजरात सरकार ने कच्छ जिला में गांधी धाम को सुरेन्द्र नगर के बजाय उसी को प्राथमिकता दी । इसीलिए दूसरा अनुमोदन नहीं हो सका ।

MR. CHAIRMAN: You have answered the question already. Mr. J. L. Bhatt.

श्री जिलेन्द्रभाई लाभशंकर भट्ट : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सुरेन्द्र नगर के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसके लिए कंसिडर करने का क्या आपका ख्याल है ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, मैं पुन: उसी प्रश्न का उत्तर दोहरा रही हूं कि राज्य सरकार ने तो सुरेन्द्र नगर का प्रस्ताव भेजा ही था, प्रस्ताव भेजा था चार लेकिन फिर गुजरात सरकार ने ही उसके लिए पहल नहीं किया और उन्होंने प्राथमिकता दे दी कच्छ में जो गांधीधाम है उसकी, तो

इसलिए भारत सरकार तो केवल अनुमोदन करती, राज्य सरकार की जब अनुशंसा आती है । हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते ।

श्री जितेन्द्रभाई लाभशंकर भट्ट : क्या आप एक और नहीं दे सकते ?

MR. CHAIRMAN: She has answered the point. Question No. 225.

Decontrol of Export of Ornaments

*225. SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some neighbouring countries of India have decontrolled export of ornaments;

(b) if so, the names of such countries with reaction of Indian Markets towards this move;

(c) whether government propose to take similar action for the exporters from India; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) हमारे कुछ पड़ोसी देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया जाता है कि नेपाल को छोड़कर, जिन्होंने आभूषणों के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन की जरूरत को हाल ही में समाप्त कर दिया है, अन्य किसी भी देश ने आभूषणों के निर्यात के बारे में पिछले कुछ दिनों में नीति संबंधी कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं किए हैं ।

(ग) तथा (घ) हमारी एक्सिम नीति में स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम के आभूषणों के निर्यात के लिए अनेक योजनाएं शामिल हैं । इन नीतियों की सतत रूप से समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, उनमें संशोधन किए जाते हैं । आभूषणों के निर्यात से न्यूनतम मूल्यवर्धन की आवश्यकता को समाप्त किए जाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सैयद सिब्ते रजी : सर, मैंने अपने सवाल में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि यह जो नेपाल में इन्होंने मिनिमम वैल्यू एडीशन को समाप्त किया है, उससे हमारे यहां जो राष्ट्रीय मार्केट है सोने की, गोल्ड ओर्नामेंट्स आदि के सिलसिले में हमारी आंतरिक मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं ? एक कंट्री की बात आपने कही है कि नेपाल ने ऐसा किया है, तो नेपाल के ऐसा करने से हमारे यहां उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या मंत्री जी कृपया बताने की कोशिश करेंगे ?

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Sir, the change in Nepal has taken place only on 19th July, 1993, that is last month. So we will have to wait. As of now, we did not have any reaction from our markets.

सैयद सिब्ते रजी : भारत में सोना भी काफी पर्याप्त मात्रा में है और मोती व डायमंड्स भी हमारे यहां काफी पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे यहां की ज्वैलरी जोकि डायमंड व पर्ल वगैरा से शृंगारित होती है क्या इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो तेजी के साथ सोने, चांदी और प्लैटीनम के गहने बिक रहे हैं, उसमें जो दूसरे कंट्रीज इनवॉल्व हैं, उनके मुकाबले में हम खड़े हो पा रहे हैं ? क्या ऐसा नहीं है कि हम इटली, हांगकांग, थाईलैंड और जर्मनी इत्यादि से इस मुकाबले में काफी पीछे हैं और हमारी जो तकनीक है, वह काफी पुरानी है और क्या भारत सरकार हमारे यहां के गोल्डस्मिथ्स को नई तकनीक के बारे में सहायता करने जा रही है ? क्या एक्सपोर्टर्स के लिए इस संबंध में कुछ खास रियायतें दी जा रही हैं ताकि वे लोग उस कंपटीशन के मुकाबले में आ सकें ? सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि वे और कौन से दूसरे कंट्रीज हैं जिनके साथ आप कॉलोबोरेशन कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्टाइज ले रहे हैं जिससे कि आप यूरोपियन कंट्रीज में भी नया मार्केट खोल सकें ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : सभापति जी, ऑर्नामेंट्स और खास तौर से गोल्ड व स्टड स्टोंस के ऑर्नामेंट्स का निर्यात काफी बढ़ रहा है । मैं ऑनरेबल मेंबर की इत्तला के लिए कहूं कि इस क्षेत्र में हमारा निर्यात टोटल निर्यात का 16 परसेंट है । पिछले साल के मुकाबले में इस साल काफी बढ़ोतरी हुई है । जहां तक नो-हाउ का सवाल है, यह अभी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम के रूप में नहीं आया है इसलिए कि बहुत-सी यूनिट्स जो ई० पी० जेड० में हैं और ई० ओ० यू० में हैं, वहां उनको सारी सुविधाएं इनपुट्स के इम्पोर्ट और सारी चीजों की हासिल है । तो जिस तरह से उनका निर्यात बढ़ रहा है उससे हम यही कह सकते हैं कि अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है । इसका मार्केट काफी बड़ा है और हर जगह जाता है । जो खालिस गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, वहां ज्यादातर गल्फ एरियाज में जाते हैं जहां कि इंडियन कम्युनिटीज इनको खरीदती हैं, लेकिन जो प्रीसियस स्टोंस स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैं, इसका काफी मार्केट है । वह अमेरिका जाता है, जर्मनी, बेल्जियम और दूसरी जगहों पर भी जाता है ।

श्री टी० एन० चतुर्वेदी : सभापति महोदय, भारतीय आभूषण दुनिया में लोकप्रिय है और उनका निर्यात बढ़ा है, इन सभी संभावनाओं को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे आभूषणों के प्रोफेशनल एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस हैं, उनकी एक बैठक बुलाएंगे ताकि उन्हें और कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसका पता लगाया जा सके और जो प्रयास मंत्रालय कर रहा है उसको और अधिक बल मिल सके ?